पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख–पत्र

वर्ष 20, अंक 1/2019

आइये जैविक खेती का संकल्प लें!

जैविक खेती का अर्थ है–बिना धरती का शोषण करे अनाज उपजाना। पहले भारत में ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती का ही चलन था। उस समय पौधों से ही खेतों के लिए खाद एवं उर्वरक तैयार कर लिए जाते थें। गाय और भैंस के गोबर से खेत को उपजाऊ किया जाता था। लेकिन आज जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और औद्योगिकरण की दौड़ ने खेती और खानपान का रुख ही बदल ड़ाला। हरित क्रांति के नाम पर खेती में नए–नए प्रयोग शुरू किए गए। अधिक अन्न उपजाने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग किया जाने लगा।

आज रासायनिक व कीटनाशकों से युक्त फसलों से मानव की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव और दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। हकीकत यह भी है कि रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग से आज किसानों को भी प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए अब फिर से जैविक खेती का चलन बढ़ रहा है। किसान समझने लगे हैं कि हमारे खाद्य पदार्थों और खेती में जहरीले रसायनों व कीटनाशकों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जैविक खेती उनके लिए समृद्धिदायक और मिट्टी के लिए फायदेमंद है। जब बड़े पैमाने पर जैविक खेती होने लगेगी तो जैविक उत्पाद उचित दामों में मिलने लगेंगे और उपभोक्ताओं तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी।

देश के कई राज्यों में किसान जैविक खेती को अपनाकर लाभान्वित हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का भी पिछले कुछ वर्षो से जैविक उत्पादों के प्रति रूझान बढ़ा है। देश में स्थानीय स्तर पर जैविक प्रक्रिया को अपनाने और बाजार उपलब्ध कराने की जरूरत है, जिससे जैविक उत्पादों का प्रचार–प्रसार हो सके। हमें राष्ट्रीय संकल्प लेना होगा कि हमारी खेती पूरी तरह जैविक पद्धति पर आधारित हो।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों के अनुदान पर अंकुश जरूरी

'प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों पर दिए जाने वाले अनुदान पर अंकुश लगाना जरूरी है।' 'कट्स' द्वारा 'प्रोओर्गेनिक–II' परियोजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय हितधारक परिचर्चा के दौरान 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने उक्त विचार व्यक्त करते हुए बताया कि रासायनिक उर्वरकों पर दिया जाने वाला अनुदान सरकार के द्वारा दूसरा बड़ा अनुदान है। जैविक खेती के क्षेत्र में विश्व स्तर पर भारत की हिस्सेदारी मात्र 2.59 प्रतिशत है।

'कट्स' द्वारा यह परियोजना स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन, स्वीडन के सहयोग से राजस्थान के दस जिलों में चलाई जा रही है। कार्यक्रम में परियोजना के अन्तर्गत अब तक की गई गतिविधियों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया, जिसमें किसान प्रशिक्षण एवं भ्रमण, जागरूकता गतिविधियां, स्कूलों में जैविक गार्डन, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट्स आदि सम्मिलित थीं। इस अवसर पर कृषि विभाग के निदेशक डॉ. एल.एन.कुमावत ने बताया कि जैविक खेती की मुहिम को उपभोक्ता, किसान और संस्थाओं को समझना होगा तथा एक साथ इसके लिए प्रयास करने होंगे।

राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र, दुर्गापुरा के निदेशक डॉ.वी.एस.यादव ने बताया कि जैविक खेती को बढ़ाने के लिए अगर हमारे पास उपलब्ध गोबर की खाद को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इनपुट की कोई समस्या नहीं रहेगी। कार्यक्रम के तकनीकी सत्र का संचालन 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने किया। कार्यक्रम में स्कूलों में बनाए गए जैविक उद्यानों में से दो सर्वश्रेष्ठ उद्यानों को पुरस्कृत किया गया।

इस अंक में...

- फाइलों में उलझी 40 करोड़ की वसूली 3
- गहरी हैं कर्जमाफी के घोटाले की जड़ें 4
- भ्रष्टाचार की रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार . 6
- देश में धरती की धधकती गर्मी से बनेगी बिजली .. 8
- देश की आधी महिलाएं खून की कमी की शिकार 10

सुरक्षित हो स्मार्ट उत्पादों की गोपनीयता

'नियामकों को यह देखने की आवश्यकता है कि स्मार्ट उत्पाद सस्ते हों और उनमें गोपनीयता सुरक्षित रहे।' 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में टेलीकॉम नियामक 'ट्राई' की सलाहकार भावना शर्मा ने मुख्यवक्ता के रूप में बोलते हुए यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि नियामकों को इस दिशा में अधिक पारदर्शिता से कार्य करने की आवश्यकता है।

वहीं 'कट्स' इटरनेशनल के महामंत्री प्रदीप महता ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में स्मार्ट फोन और गैजेट के संबंध में ई-कॉमर्स और उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में बताया। 'कट्स' इंटरनेशनल के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने परिचायक संबोधन में स्मार्ट उत्पादों की उपलब्धता, डाटा एवं निजी सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उपभोक्ताओं की चिंताओं से अवगत कराया। वोडाफोन-आइडिया के सहायक मैनेजर अभिषेक खांडल ने उपभोक्ताओं से स्मार्ट उत्पादों के प्रयोग के लिए अपने आप को तैयार करने और अपने व्यक्तिगत डाटा के दौरान सचेत रहने को कहा क्योंकि इससे जानकारी लीक होने की ज्यादा संभावना रहती है।

संगोष्ठी के दौरान 'कट्स' द्वारा स्मार्ट उत्पादों के बारे में कराए गए सर्वेक्षण से उभरे तथ्यों को रखा गया। कार्यक्रम में उपभोक्ता अधिकारों पर कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं, ई-प्लेटफार्म एवं सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ ही विधिक विशेषज्ञों ने भी भाग लिया।

बाल सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण भावी विकास के दो मुख्य स्तम्भ: मेनका गांधी

'बाल सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण देश के भावी विकास के दो मुख्य स्तम्भ हैं। इस आधी आबादी द्वारा भारत की प्रगति और विकास में दिए गए मूल्यवान योगदान की यूं ही उपेक्षा नहीं की जा सकती।' केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने 'कट्स' द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'स्टोरीज ऑफ चेंज' पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह कहा।

उन्होंने दक्षिणी राजस्थान के ज्यादातर गांवों में बाल सुरक्षा व महिलाओं के लिए व्यावसायिक अवसर पैदा करने में 'कट्स' मानव विकास केंद्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में पुरुष वर्ग को बालिका सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर और अधिक संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। सामाजिक असमानताओं को मात्र अवसरों की समानता लाकर ही दूर किया जा सकता है।

इस अवसर पर 'कट्स' के महामंत्री प्रदीप महता ने कहा कि जब महिला सशक्त होती है तो इसका सीधा लाभ परिवार को मिलता है एवं उत्तरोत्तर प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचता है। 'स्टोरीज ऑफ चेंज' पुस्तक में 'कट्स' मानव विकास केंद्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा पिछले 25 वर्षों में राजस्थान में जमीनी स्तर पर बाल सुरक्षा एवं स्वयं सहायता समूहों के गठन में दिए गए सक्रिय योगदान तथा महिलाएं किस तरह आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनी हैं, के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया है। परिचर्चा के दौरान स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए।

'कट्स' मानव विकास केंद्र सम्मानित

जयपुर स्थित हरिशचंद्र माथुर प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में 'कट्स' मानव विकास केंद्र, चित्तौड़गढ़ को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ संस्था पुरस्कार से नवाजा गया है। समारोह में मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने 'कट्स' के कार्यक्रम अधिकारी मदनलाल कीर को शाल ओढ़ाकर, प्रशस्ति-पत्र एवं 15 हजार रुपए नकद राशि से सम्मानित किया।

'कट्स' को यह पुरस्कार चित्तौड़गढ़ जिले में विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने, उन्हें आयजनक गतिविधियों और सरकारी योजनाओं से जोड़ने में सर्वश्रेष्ठ काम करने पर दिया गया है। इस अवसर पर मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान से जुड़े उदपुरा गांव के पूरण मल शर्मा और बापू बस्ती निम्बाहेड़ा के गोविन्द रेगर को भी शाल ओढ़ाकर प्रशस्ति-पत्र व दस हजार रुपए की नकद राशि से सम्मानित किया गया।

कर्ज बांटने में बैंक लक्ष्य से पीछे

कृषि और लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कर्ज का निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में देश का बैंकिंग क्षेत्र असफल रहा है। यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जारी किया है। हालांकि सरकारी बैंकों ने खेती के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया लेकिन निजी और विदेशी बैंक इसमें असफल रहे।

सरकारी बैंकों के लिए यह लक्ष्य 18 फीसदी, निजी बैंकों के लिए 16.2 फीसदी और विदेशी बैंकों के लिए 16.7 फीसदी है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि के लिए कर्ज लक्ष्य पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कर्जमाफी की योजनाओं का भी प्रभाव पड़ा है।

सालाना आधार पर कर्ज में बढ़ोतरी 3.8 फीसदी रही। हालांकि संसदीय समिति ने एनपीए पर नजर रखने के लिए एक समिति बनाने का सुझाव दिया है। *(रा.प., 04.01.19)*

खाद बनी नहीं, मशीनें कबाड़ हो गई

राजधानी जयपुर के 1100 पार्कों में से रोजाना 400 मीट्रिक टन करीब ग्रीन वेस्ट निकलता है। चंडीगढ़ व पंजाब में जहां बहु तादात में निकलने वाले ग्रीन वेस्ट से उच्च गुणवत्ता की खाद तैयार की जा रही है, वहीं जयपुर में हर साल लाखों मीट्रिक टन ग्रीन वेस्ट बरबाद हो रहा है। जबकि नगर निगम ने कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कंपोस्ट प्लांट पार्कों में लगाए हुए हैं।

शहर के 100 गार्डनों में बनाए गए ये कंपोस्ट खाद के प्लांट बेकार पड़े हैं। निगम ने करीब सवा करोड़ रुपए खर्च कर कंपोस्ट खाद बनाने की 70 मशीनें लगाई थी, ताकि पार्कों से उत्पन्न होने वाले ग्रीन वेस्ट को रिसाइकिल किया जा सके और खाद का उपयोग गार्डन को हरा-भरा रखने में किया जा सके।

गौरतलब यह है, लापरवाही के चलते कंपोस्ट खाद बनाने की मशीनें आज तक काम में नहीं ली गई और 100 गार्डनों से एक भी परात खाद तैयार नहीं हुई। *(दै.भा., 29.03.19)*

प्रदेश में हर छठा व्यक्ति बेरोजगार

राजस्थान में बेरोजगारी के हालात काफी चिंताजनक हैं। बेरोजगारी की स्थिति में राजस्थान चौथे पायदान पर पहुंच गया है। यहां तक कि बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों की स्थिति राजस्थान से बेहतर है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी की दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का हर छठा व्यक्ति बेरोजगार है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर पिछले तीन साल में सबसे ऊपरी शिखर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन संकट ने बेरोजगारी बढ़ाई है।

प्रदेश में इस समय बेरोजगारी दर 15 फीसदी है। देश के त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य ही बेरोजगारी में राजस्थान से ऊपर है। राज्य में बेरोजगारी की यह स्थिति राष्ट्रीय औसत से भी दोगुनी है। *(दै.भा., 14.01.19)*

घोटाले की जांच से कतरा रहे अफसर

सहकारी बैंकों में घोटाले दर घोटाले सामने आ रहे हैं लेकिन जांच के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। ऐसा ही एक मामला अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक (सीबीसी) में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले का है, जिसमें दो कमेटी गठित होने के बाद भी जांच शुरू नहीं हुई। अब तीसरी कमेटी गठित कर विभाग ने उससे उम्मीद बांधी है।

अलवर सीबीसी में यह घोटाला वर्ष 2014 से 2018 के बीच रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट (आरटीजीएस) एवं नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से होने वाले लेनदेन में हुआ। कहा जा रहा है कि बैंक में कार्यरत आईटी कर्मचारियों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने दूसरे बैंकों में खाते खोले और बैंक के खाते से रकम आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से अपने खातों में जमा कर ली। *(रा.प., 25.03.19)*

मिड-डे मील का 17 टन गेहूं पकड़ा

बाड़मेर जिले में धोरीमन्ना से आ रहा 17 टन गेहूं से भरे ट्रक को बोरानाडा थाना पुलिस ने पकड़ा। आशंका जताई जा रही है कि यह गेहूं स्कूली बच्चों के मिड-डे मील का है। पुलिस के अनुसार ट्रक में 340 कट्टों में 17 हजार 20 किलो यानि सत्रह टन बीस किलो गेहूं भरा मिला। ट्रक चालक ने यह गेहूं धोरीमन्ना से बोरानाडा में फूड एग्रो पार्क स्थित एक फैक्ट्री में सप्लाई होने की जानकारी दी।

लेकिन उस फैक्ट्री से संपर्क किया तो संचालक ने ऐसे गेहूं मंगवाने की जानकारी से साफ इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने गेहूं संदिग्ध मानकर जब्त कर लिया। धोरीमन्ना थाना पुलिस, बाड़मेर का जिला रसद विभाग व शिक्षा विभाग इसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही कालाबाजारी के बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। *(रा.प., 28.03.19)*

फाइलों में उलझी 40 करोड़ की वसूली

प्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार के समय सरपंच व ग्रामसेवकों ने मनमर्जी से करोड़ों रुपए की सोलर लाइटें लगा दी। सोलर लाइट की कीमत 22-23 हजार तय थी, लेकिन भुगतान 53 हजार रुपए तक कर दिया गया। जब सरकार ने जांच कराई तो घपले का खेल उजागर हुआ। इस दौरान सभी जिला परिषदों में विशेष अभियान के तहत जांच भी हुई और प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली निकाली गई।

भाजपा के सत्ता में आते ही यह मामला खूब तूल पकड़ा। नेताओं ने वसूली करने की बात भी कही। 43 में से 3 करोड़ रुपए की वसूली भी हुई। लेकिन सरपंचों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया। इसके बाद कार्रवाई और नोटिस की फाइल कागजों में ही दफन हो गई। अब सरकारी मेहरबानी के चलते ग्राम सेवकों व सरपंचों से 40 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो पा रही है। *(रा.प., 21.02.19)*

गहरी हैं कर्जमाफी के घोटाले की जड़ें

सहकारी बैंकों में कर्जमाफी घोटाले के खुलासे होते जा रहे हैं। डूंगरपुर के बाद अब बांसवाड़ा में भी शिकायतें आने लगी हैं। किसानों को जानकारी नहीं है और उनके नाम से लोन उठा लिया गया और वह माफ भी हो गया।

घोटाले की जड़ें गहरी देखकर अतिरिक्त रजिस्ट्रार के नेतृत्व में गठित की गई पांच टीमें बिना किसी नतीजे के वापस लौट आईं। अब सरकार ने सभी सहकारी समितियों की ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए अकेले डूंगरपुर में बीस टीमें भेजने का निर्णय लिया गया है। कर्जमाफी का यह घोटाला पहले बार सागवाड़ा में सामने आया, जब किसानों को पता चला कि उनके नाम से किसी ने लोन उठाया था, जो कर्जमाफी 2018 योजना में माफ हो गया। इस तरह का घोटाला अन्य जिलों में भी हो सकता है। *(रा.प., 16.01.19)*

बुनियादी परियोजनाओं की लागत बढ़ी

देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की डेढ़ सौ करोड़ रुपए से अधिक की 363 परियोजनाओं की लागत में 3.42 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देरी और अन्य कारणों से इन परियोजनाओं की लागत बढ़ी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वय मंत्रालय की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वय मंत्रालय 150 करोड़ रुपए व उससे अधिक की ढांचागत परियोजनाओं की निगरानी करता है। मंत्रालय की अक्टूबर 2018 के लिए जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,452 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक लागत 18,27,757.29 करोड़ रुपए थी, जिसकी अनुमानित लागत अब 21,70,036.32 करोड़ रुपए हो गई है। *(न.नु., 05.02.19)*

आचार संहिता में फंसा गरीब का गेहूं

भाजपा व कांग्रेस सरकार की आपस की राजनीति में पूरे प्रदेश के हजारों गरीब परिवारों को एक रुपए किलो में मिलने वाला गेहूं और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज अटक गया है। ऐसा भामाशाह कार्ड पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो छपा होने के वजह से हुआ है।

प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद कार्डों को डिब्बे में बंद कर पटक दिया गया है। यह भी सामने आ रहा है कि अब यह कार्ड नहीं बांटे जाएंगे। क्योंकि, अब सरकार बदल गई है। बुजुर्ग, विकलांग व विधवा पेंशन आदि के लिए भी भामाशाह कार्ड जरूरी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अब ई-मित्र के जरिए भामाशाह कार्ड फोटो रहित बनाए जाएंगे। *(रा.प., 31.03.19)*

शो-पीस बनी ई-मित्र प्लस मशीनें

प्रदेश में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए पिछली सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपए खर्च कर लगाई गई ई-मित्र प्लस मशीनें विभाग की मॉनिटरिंग की कमी के चलते शो-पीस बनकर रह गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अटल सेवा केंद्रों में लगी करीब 10 हजार मशीनों में से ज्यादातर बंद पड़ी है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का दावा था कि ग्रामीणों को इस मशीन से 24 घंटे 270 से भी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इन मशीनों के चालू नहीं होने से जमाबंदी निकलवाना, विवाह, मूल निवास, जाति और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, राशन कार्ड व आधार कार्ड बनवाना, ऑनलाइन शिकायत करना जैसी अनेक सुविधाओं और सेवाओं से ग्रामीण वंचित हैं। *(दै.भा., 28.03.19)*

मदिरा समूह आंवटन में घोटाला

शराब ठेकेदारों को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाने के मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने जयपुर जिला आबकारी कार्यालय पर छापा मारकर रेकॉर्ड जब्त किया है। विभाग ने देशी शराब के 38 मदिरा समूहों को करीब 22 करोड़ रुपए धरोहर राशि जमा नहीं कराए जाने के बाद भी ठेका चलाने की अनुमति जारी कर दी थी।

जबकि ऐसे ही एक मामले में गारंटी की राशि जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त किया गया था। विभाग की इस दोहरी कार्य प्रणाली से करीब 22 करोड़ रुपए का राजस्व समय पर जमा नहीं कराया गया। इससे विभाग को भारी ब्याज का नुकसान हुआ। राशि करीब पांच माह बाद जमा कराई गई। *(रा.प., 20.01.19)*

फाइलों में दबा रहा ऑर्गेनिक बोर्ड

प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुए प्रयास 5 साल से फाइलों में दबे हुए हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसके लिए राजस्थान ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड (आरओबीसी) के गठन की घोषणा की थी। लेकिन पांच साल बाद भी यह फाइलों से बाहर नहीं निकला।

भाजपा सरकार ने जैविक खेती निदेशालय बनाने की तैयारी की लेकिन यह निदेशालय भी नहीं बन पाया। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अब कांग्रेस सरकार इस घोषणा को पूरा करेगी। इससे प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को काफी राहत मिलेगी। *(दै.भा., 31.01.19)*

आंकड़े छिपाने पर उठ रहे हैं सवाल

देश के महत्वपूर्ण आंकड़े छिपाने को लेकर सरकारें सवालों में घिरी रहती हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं अपराध, किसानों की आत्महत्या, जाति और बच्चों में पोषण जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सरकारी रिपोर्टें काफी समय से सार्वजनिक नहीं की गई है।

ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर इन आंकड़ों में ऐसा क्या है जिसे बताने से सरकारें डरती हैं। किसानों की आत्महत्या का मामला देश में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी की जाने वाली दुर्घटनाएं और आत्महत्या के आंकड़े भी पिछले चार वर्षों से जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा यूपीए सरकार के समय से ही रोजगार और जाति के आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। *(रा.प., 01.02.19)*

एसीबी की आधी-अधूरी कार्रवाई

प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारी भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ आधी-अधूरी कार्रवाई कर जांच के नाम पर खानापूर्ति करने में लगे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे अफसरों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों में एसीबी सालों से कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट तक पेश नहीं कर पाई।

प्रदेश के इन आधी-अधूरी कार्रवाई के मामलों में एकल पट्टा प्रकरण, नकली घी प्रकरण, खान घूसकांड, एनआरएचएम और जलदाय विभाग घूसकांड की जांच कई माह से पेंडिंग हैं, जिनमें कई आला अफसरों के नाम जुड़े हुए हैं। एसीबी के अफसरों ने इनके खिलाफ एक दफा तो कोर्ट में चालान पेश कर दिया, लेकिन उन मामलों की फाइलों को वापस ही नहीं संभाला। *(दै.भा., 11.01.19)*

कालेधन की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं

वित्त मंत्रालय ने कालेधन पर उन तीन रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है, जिनमें भारतीयों के देश के भीतर और विदेश में कालाधन रखने से जुड़ी जानकारी है। मंत्रालय का कहना है कि इन रिपोर्ट की जांच एक संसदीय समिति कर रही है, ऐसे में उन्हें सार्वजनिक करने से संसद के विशेषाधिकारों का हनन होगा।

सरकार के पास ये रिपोर्ट जमा हुए चार साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई एक सूचना के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 (1)(सी) के तहत इससे जुड़ी सूचना नहीं देने की छूट का प्रावधान है। इस धारा के तहत कोई भी ऐसी सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती जिससे संसद के अधिकारों का हनन हो। *(न.नु. एवं दै.भा., 05.02.19)*

जस्टिस घोष बने पहले लोकपाल

जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी आयोग के न्यायिक सदस्य बनाए गए हैं। जबकि दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेन्द्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम इसके गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस घोष लोकपाल बनाए जाने से पहले मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे। वह सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं।

भ्रष्टाचार की सही तरीके से जांच के लिए लोकपाल बनाने के अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद 2013 में केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कानून बना था। कानून बनने के पांच साल बाद यह नियुक्ति होने जा रही है। *(रा.प., 20.03.19)*

एसीबी की बड़ी जंग लड़ने की तैयारी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने हाल ही प्रदेश में नारकोटिक्स विभाग के अतिरिक्त आयुक्त सहीराम मीणा के काले कारनामों, सीबीआई इंस्पेक्टर प्रकाश चंद का घूसकांड तथा झोटवाड़ा एसीपी आस मोहम्मद की देखरेख में चल रहे रिश्वत के खेल जैसे बड़े मामलों का खुलासा कर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ने की कोशिश शुरू की है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग एसीबी के कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं।

आमजन अपनी परेशानी से बचने और रिश्वतखोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए एसीबी से आस लगाता है। लेकिन एसीबी में जांच अधिकारियों की संख्या कम होने के कारण उनके हौसले कमजोर पड़ जाते हैं। इस कमी से निपटने के लिए एसीबी ने 100 दिवस की कार्ययोजना बनाई है। *(दै.न., 03.02.19)*

8500 करोड़ का कालाधन उजागर

आयकर विभाग ने प्रदेश में 8500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कालेधन का खुलासा कर नया इतिहास रचा है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में आयकर विभाग ने कुल 1758 करोड़ रुपए का कालाधन उजागर किया था।

प्रदेश में आयकर विभाग ने 5000 लोगों की सूची तैयार की है। आयकर विभाग ब्लैकमनी मेकर्स के खिलाफ छापे की कार्रवाई शुरू कर सकता है। खास बात यह है कि पिछले वित्त वर्ष में कुल 276 छापे और सर्वे किए, जबकि इस वित्त वर्ष में केवल 195 कार्रवाई हुई। हाल ही में आई नेशनल काउंसिल एप्लाइड रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों का कालाधन 95 फीसदी देश में ही है। जबकि केवल पांच फीसदी विदेशों में है। *(रा.प., 09.03.19)*

अब फिर बढ़ने लगी धर-पकड़

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में रंगे हाथ रिश्वत लेने के मामलों पर गौर करें तो वर्ष 2016 व 2017 के मुकाबले 2018 में ट्रेप की कर्रवाई घट गई है। वर्ष 2016 में 290 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। वर्ष 2017 में 291 रिश्वतखोर धरे गए। जबकि वर्ष 2018 में यह आंकड़ा घट कर 246 रह गया।

अब वर्ष 2019 में फिर धर-पकड़ तेज हुई है। यहां तक कि नारकोटिक्स के अतिरिक्त आयुक्त रहे सहीराम मीणा को रिश्वत लेते पकड़कर एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। *(रा.प., 11.02.19)*

बेनामी संपत्ति के सबसे ज्यादा मालिक नौकर

नौकरों के नाम से बेनामी संपत्तियां खरीदने में राजस्थान के व्यापारी पूरे देश में पहले नंबर पर है। प्रदेश में बेनामी संपत्तियों से जुड़े मामलों में आयकर विभाग ने 200 से ज्यादा मामले पकड़े हैं, जिनमें नौकरों, पूर्व नौकरों या उनके रिश्तेदारों के नाम से करोड़ों रुपए की जमीनों की खरीद हुई है। इन जमीनों का बाजार भाव एक हजार करोड़ से भी ज्यादा है। प्रदेश में कुल 362 बेनामी संपत्तियों के प्रोविजनल अटैचमेंट हुए हैं।

आयकर विभाग को बेनामी संपत्तियों को जब्त कर सीज करने का अधिकार है। वर्ष 2016 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सात साल की सजा का भी प्रावधान है तथा गलत सूचना देने वाले पर संपति के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने की व्यवस्था है। *(दै.भा., 04.03.19)*

भ्रष्टाचार की रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार

भारत में भ्रष्टाचार में कमी आई है और भ्रष्ट देशों की रैंकिंग में भारत की स्थिति सुधरी है। यह बात गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की 2018 की सालाना रैंकिंग में सामने आई है। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की जारी ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स-2018 में 180 देशों में भारत तीन स्थान के सुधार के साथ 78वें स्थान पर है। जबकि 2017 में भारत 81वें स्थान पर था। चीन 87वें और पाकिस्तान117वें स्थान पर है। श्रीलंका और इंडोनेशिया 89वें, नेपाल और मालदीव 124वें, म्यामार 132वें, ईरान, मैक्सिको और रूस 138वें, बांग्लादेश 149वें, अफगानिस्तान 172वें और उत्तर कोरिया 176वें स्थान पर है। डेनमार्क, न्यूजीलैंड व फिनलैंड में सबसे कम भ्रष्टाचार है।

जबकि सबसे भ्रष्ट सोमालिया, सीरिया और दक्षिणी सूडान रहे हैं। इंडेक्स में 2011 के बाद पहली बार अमेरिका चार स्थान फिसल कर 20 देशों की सूची में बाहर हो गया है। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि आगामी चुनावों की ओर बढ़ रहे भारत ने इंडेक्स में 2017 के 40 अंक में सुधार करते हुए 2018 में 41 अंक हासिल किए हैं। संस्था ने कहा, '2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन ने जोर पकड़ा था और जन लोकपाल की मांग उठी थी, यह बाद में कमजोर पड़ गई। *(दै.भा., 30.01.19)*

ऐसे होती है रैंकिंग

भ्रष्टाचार सूचकांक तैयार करने के लिए देशों को 0 से 100 अंक के बीच अंक दिए जाते हैं। सबसे कम अंक सबसे अधिक भ्रष्टाचार का संकेत माना जाता हैं।

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
चित्तौड़गढ़	हिम्मतलाल दीपक	सहायक सचिव, पांडोलाई पंचायत समिति, कपासन तकनीकी सहायक अभियंता, मनरेगा	20,000	दै.भा., 03.01.19
अजमेर	राजेन्द्र सिंह राठौड़	प्लॉट मैनेजर, को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन	40,000	रा.प., 09.01.19
जयपुर	डॉ. चिराग भंडारी	डायरेक्टर, वेदान्त इंजीनियरिंग कॉलेज, कानोता	30,000	रा.प. एवं दै.भा., 21.01.19
जोधपुर	महेंद्र चौधरी	भू-राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग	50,000	दै.भा., 23.01.19
कोटा	राकेश महेश	सरपंच पुत्र, सातलखेड़ी पंचायत समिति कर्मचारी, सातलखेड़ी पंचायत समिति	25,000	दै.भा., 24.01.19
भरतपुर	राकेश कुमार मीणा	सीनियर सेक्शन इंजीनियर, रेलवे, आगरा (ईदगाह)	85,000	दै.भा. एवं रा.प., 06.02.19
अलवर	रमेश चन्द मीणा	सहायक अभियंता, बिजली निगम, नीमराना	1,00,000	दै.भा. एवं दै.न., 08.02.19
बांसवाड़ा	रमेश चन्द्र गामोट	भू-अभिलेख निरीक्षक, परतापुर पटवार मण्डल	60,000	रा.प. एवं दै.न., 09.02.19
अलवर	रमेश प्रसाद चौरसिया मैनपाल यादव	असिस्टेंट अकाउंट ऑफीसर, सीएजी ऑडिट टीम सीनियर अकाउंटेन्ट, सीएजी ऑडिट टीम, नई दिल्ली	20,000	दै.भा एवं रा.प., 09.02.19
टोंक	जगदीश प्रसाद जाट	पटवारी, तहसील कार्यालय परिसर, टोंक	10,000	रा.प. एवं दै.न., 09.02.19
झालावाड़	मोरम बाई	पंचायत समिति प्रधान, मनोहरथाना, झालावाड़	15,000	दै.भा., 16.02.19
कोटा	रामकुमार मेहता	पूर्व अध्यक्ष, कोटा नगर विकासन्यास, कोटा	5,00,000	दै.भा. एवं रा.प., 16.02.19
जयपुर	तेजकुमार अजमेरा	एलडीसी, जयपुर कथक केंद्र, जयपुर	8,000	दै.भा. एवं दै.न., 19.02.19
भरतपुर	जगमोहन सिंह	एएसआई, नदबई थाना, भरतपुर	10,000	दै.भा. एवं दै.न., 21.02.19
जयपुर	राजकुमार चौधरी	सुरक्षा अधिकारी, राज्य बीमा निगम, जयपुर	10,000	रा.प. एवं दै.भा., 07.03.19
जयपुर	प्रकाश चन्द शांतिलाल आंचलिया	इंस्पेक्टर, सीबीआई अफसर दलाल	75,00,000	दै.भा., 09.03.19
जयपुर	अमित कुमार पारीक	सहायक ट्रेजरी ऑफिसर, पेंशन विभाग	10,000	रा.प. एवं दै.भा., 28.03.19
अजमेर	मोहनलाल पाराशर	कनिष्ठ लिपिक, राजस्व शाखा, अजमेर	15,000	दै.भा., 29.03.19

बीस फीसदी कम हो गई खेती की जमीन

पौधों, जानवरों और सुक्ष्म जीवों पर हुए संयुक्त राष्ट्र के पहले अध्ययन के अनुसार, जैव विविधता की रक्षा में विफलता के कारण खाद्य उत्पादक भूमि की क्षमता कम हो रही है। जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता को कहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र से जुड़े खाद्य और कृषि संगठन के वैज्ञानिकों ने अपने ताजा अध्ययन में इस बारे में चेतावनी जारी की है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक, परागण में सहायक भौंरों और तितलियों जैसे कई जीवों का अस्तित्व खतरें में है। इसके अलावा पिछले दो दशकों में दुनिया की 20 प्रतिशत खेती योग्य जमीन कम हो गई है, साथ ही 6000 खेती की प्रजातियों में से कई तेजी से विलुप्त हो रही हैं। *(रा.प., 25.02.19)*

बढ़ रहा है डिजिटल खेती का चलन

कृषि क्षेत्र में बढ़ती जा रही समस्याओं और अनिश्चितताओं के बीच डिजिटल खेती को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। खर्चीला होने के बावजूद भारत सहित कई एशियाई देशों में इसकी ओर किसानों का रुझान बढ़ रहा है।

डिजिटल खेती में स्वतः काम करने वाले यंत्र, ड्रोन, जीपीएस और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) जैसी तकनीकों की मदद से खेती की जाती है। डिजिटल खेती में बुवाई से लेकर कटाई तक की प्रक्रिया को बढ़ावा देने सहित लगभग हर जानकारियां शामिल हैं। नई तकनीकों और उपकरणों के इस्तेमाल के चलते इसमें शुरुआती लागत तो ज्यादा आती है, पर लंबे समय में खेती की लागत काफी घट जाती है। *(रा.प., 03.03.19)*

आरक्षण बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

लोकसभा व राज्यसभा की स्वीकृति के बाद सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है।

इसी के साथ मोदी सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे बिल ने कानूनी रूप ले लिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जल्द ही आरक्षण के प्रावधानों से जुड़े नियम-कायदों को अंतिम रूप दे देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यह देश की युवा शक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा तथा देश में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा।

(दै.भा., 12.01.19)

गायें देंगी अब केवल बछड़ी को जन्म

पशुपालक के लिए अत्याधुनिक तकनीक से होने वाले कृत्रिम गर्भाधान से अब गायें केवल बछड़ी को ही जन्म देंगी। इस तकनीक का मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश व हरियाणा के पशुपालक उपयोग कर रहे हैं। इससे उनके डेयरी फार्मों में गायों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अच्छी नस्लों की गायों के जीन मिलने से बछड़ियों के दूध देने की मात्रा भी पुराने पशुओं से अधिक है। यह तकनीक उन्नत किसानों को काफी राहत दे रही है।

अमरीकी कंपनी ने इसके लिए अब पूणे में प्लांट स्थापित कर दिया है। इससे गायों की विभिन्न प्रजाति के हिसाब से एक से दो हजार रुपए में पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमन सेम्पल उपलब्ध हो सकता है।

(रा.प., 11.03.19)

पांच लाख तक की आय कर मुक्त

मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए करदाताओं को लुभाने के लिए अंतरिम बजट में पांच लाख रुपए तक की वार्षिक कर योग्य आय वाले करदाताओं को टैक्स में पूरी छूट दी है। अर्थात उन्हें पांच लाख रुपए की कुल आय पर टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जिनकी पांच लाख रुपए से अधिक आय है तो उन्हें पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर देना होगा। पांच लाख से ज्यादा वेतन पाने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार रुपए था, इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है। बैंक और डाकघर में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस से छूट की सीमा भी 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दी गई है।

नौकरीपेशा लोगों को केंद्रीय बजट में बड़ी राहत दी गई है। वेतनभोगी कर्मचारी विभिन्न छूटों का फायदा उठाकर 10.10 लाख रुपए तक की कमाई पर आयकर बचा सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी लिमिट को डबल कर दिया गया है। ग्रेच्यूटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत पहले यह दस लाख रुपए थी जिसे अब बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। मध्यमवर्ग व छोटे कारोबारियों को भी कई योजनाओं के तहत लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए अपने घर का सपना साकार करने के मकसद से टैक्स और बैंक ऋणों पर ब्याज दर में राहत दी गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मेगा पेंशन योजना लाई गई है। लोकसभा में वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने बजट भाषण में साफ कहा है कि टैक्स में बदलाव के प्रावधान नई सरकार ही लागू करेगी। अर्थात सभी घोषणाएं नई संसद में पास होने के बाद लागू होगी।

किसानों की झोली खुशियों से भरी

केंद्रीय अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान योजना से दो हैक्टेयर भूमि वाले किसान परिवार को सालाना 6000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। यह राशि दो-दो हजार रुपए की तीन किश्तों में मिलेगी। योजना एक दिसंबर 2018 से लागू मानी गई है। पहली किश्त 31 मार्च तक मिल जाएगी। इस योजना में वर्ष 2018-19 के लिए 20 हजार करोड़ व 2019-20 के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्राकृतिक आपदा पर पीड़ितों को 2 फीसदी और फसल ऋण का समय पर भुगतान करने पर 3 फीसदी छूट दी जाएगी।

राज्य विधानसभा में जुलाई 2019 तक के लिए पारित लेखानुदान में सरकार द्वारा पूर्व में घोषित किसानों की कर्जमाफी योजनाओं को फिर से दुहराते हुए उन्हें पेंशन देने और सहकारिता से जुड़े दुग्ध उत्पादक किसानों को एक फरवरी से दुग्ध संकलन पर दो रुपए प्रति लीटर की दर से बोनस देकर राहत देने की घोषणा की गई है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार नई नीति बनाएगी।

देश में धरती की धधकती गर्मी से बनेगी बिजली

केंद्र सरकार के मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में चर्चित रीवा के अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्लांट में बड़ा प्रयोग शुरू हुआ है। बदवार पहाड़ में स्थापित 750 मेगावाट के प्लांट में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब देश में पहली बार जमीन से निकलने वाली ऊष्मा से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है।

इसके तहत प्लांट से सोलर मीटर लगाकर टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। सोलर प्लांट में अभी केवल आसमान की ओर प्लेट लगाई गई है। आगे चलकर इनके नीचे भी प्लेट जगाई जाएंगी, ताकि भूमि से उत्सर्जित ऊष्मा से बिजली बनाई जा सके। उम्मीद है इससे 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त बिजली का उत्पादन शुरू होगा। प्लांट के इंजिनीयरों ने बताया कि सोलर मीटर के सहारे पता लगाया जा रहा है कि भूमि से गर्मी किस मौसम में किस तीव्रता के साथ निकलती है। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि होगी। *(रा.प., 30.01.19)*

बिजली सिस्टम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग

जयपुर शहर में अब बिजली सप्लाई, फॉल्ट, ट्रिपिंग, वोल्टेज व लोड की हाईटेक व ऑनलाइन तरीके से मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए शहर में बिजली के फीडर, ट्रांसफार्मर व मोटराइज्ड रिंग मैन यूनिट (आरएमयू) पर 600 फीडर रिमोट टर्मिनल यूनिट (एफआरटीयू) लगाए हैं।

अब स्काडा के कंट्रोल रूम से ही उपभोक्ता की बिजली सप्लाई की मॉनिटरिंग होगी। फाल्ट होते ही स्काडा (सुपरवाइजिंग कंट्रोल एंड डेटा एक्वीजिएशन) में जानकारी लग जाएगी। कंट्रोल रूम से ही कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम से उस फाल्ट की लाइन को सिस्टम से हटाकर शेष इलाके को चालू कर दिया जाएगा, ताकि कम उपभोक्ता प्रभावित हों। अब स्काडा कंट्रोल रूम से ही बिजली सप्लाई चालू व बंद की जा सकेगी। फाल्ट के बारे में भी पता लग सकेगा। इससे उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा।

(दै.भा., 16.02.19)

बिजली समस्या पर त्रिस्तरीय व्यवस्था

राज्यों में बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सामान्य उपभोक्ता को गलत व बढ़ा हुआ बिल, खराब मीटर, फाल्ट रिपेयर न होना, कनेक्शन नहीं मिलना, बिजली काट देना, राशि रिफण्ड न होना जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे पहले चरण में इलाके के एरिया ऑफीसर के पास शिकायत दर्ज करानी होती है। यदि यहां समस्या हल नहीं होती है, तो दूसरे चरण में आप नोडल ऑफीसर के पास निर्धारित फॉर्म में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें पहले दर्ज शिकायत का ब्योरा भी देना होगा।

यहां से भी राहत नहीं मिलने पर तीसरे चरण में आप बिजली विभाग के उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां भी आपको पिछली कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। अगर यहां भी समाधान नहीं हो तो आपके पास बिजली लोकपाल के समक्ष अपील करने का विकल्प खुला होता है। यहां से भी निराशा महसूस होने पर आप जिला उपभोक्ता फोरम या न्यायालय में जा सकते हैं। *(दै.भा., 13.03.19)*

जयपुर डिस्कॉम नंबर वन

देशभर की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में सबसे कम बिजली कटौति में जयपुर डिस्कॉम ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं उपभोक्ताओं द्वारा ई-पेमेंट में चौथे स्थान पर रहा है। भारत सरकार के पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने बिजली कंपनियों की रेटिंग जारी की है।

इसे जयपुर डिस्कॉम की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पीएफसी के ऊर्जा एप में हर महीने छह मापदंडों-लम्बित शिकायतें, कटौति की औसत अवधि, पॉवर कट की संख्या, लम्बित कनेक्शन, उपभोक्ता की ओर से किए गए ई-पेमेंट तथा बिजली चोरी के आंकड़ों के आधार पर रेटिंग दी जाती है। डिस्कॉम के एमडी ए.के.गुप्ता ने बताया कि उपभोक्ता सेंवाओं को बेहतर करने के लिए इंजीनियरों की टीम के साथ अच्छा काम करने की कोशिश की जा रही है। *(दै.भा., 14.02.19)*

जारी होंगे एक लाख कृषि कनेक्शन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली विभाग के अफसरों को आदेश दिए हैं कि प्रदेश में जून माह तक एक लाख किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किए जाएं। किसानों को कृषि कनेक्शन डिमांड राशि जमा कराने पर दिए जा सकेंगे। सौभाग्य योजना से वंचित रहे ग्रामीणों को भी मार्च तक कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि दूर-दराज के क्षेत्रों में सौर-ऊर्जा के माध्यम से घरों तक रोशनी पहुंचाने के काम में तेजी लाई जाए तथा 60 हजार कनेक्शन देने के लक्ष्य को तय समय में पूरा किया जाए। अधिकारियों को कहा गया है कि सुबह 7 से 11 बजे और शाम को 6 से 10 बजे तक घरेलू बिजली की आपूर्ति में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए साथ ही सिंचाई के लिए बिना ट्रिपिंग विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। *(दै.न., 21.01.19)*

सरचार्ज के नाम पर मनमानी वसूली

जयपुर डिस्कॉम अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 तक उपभोग की गई बिजली पर फ्यूल सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से बिलों में 100 रुपए से 500 रुपए तक की ज्यादा वसूली करेगा। हर यूनिट बिजली खर्च पर 37 पैसे का फ्यूल सरचार्ज लगेगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए है।

अब आगामी अप्रेल से मिलने वाले बिलों में फ्यूल सरचार्ज की राशि जुड़कर आएगी। बिजली कंपनियां फ्यूल सरचार्ज के आधार पर करीब 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली करेंगी। जयपुर डिस्कॉम अपने उपभोक्ताओं से 120 करोड़ रुपए की वसूली करेगा। डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर (हैडक्वार्टर) राजीव चौधरी ने बताया कि आरईआरसी के निर्देशानुसार ही फ्यूल सरचार्ज वसूल रहे हैं। *(दै.भा., 14.03.19)*

पानी सहेजने में चल रही मनमानी

पेयजल किल्लत का स्थाई हल खोजने के बजाय अफसर धरती को छलनी करने पर तुले हैं, जबकि पानी सहेजने पर कोई ध्यान ही नहीं है। शहर में स्टॉर्मवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो बनाए, मगर नौकरशाहों का ज्यादा ध्यान पानी सहेजने के बजाय आंकड़े बढ़ाने पर रहा।

नतीजतन, हार्वेस्टिंग सिस्टम उपयोगी ही नहीं हो पाए और भूजल का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। बताया जा रहा है कि जयपुर शहर में 221 स्टॉर्मवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जिनमें से ज्यादातर की सफाई नहीं होने से बारिश का लाखों लीटर पानी जमीन के बजाय नालों में बह रहा है। इस बीच भवनों में वर्षा जल पुनर्भरण स्ट्रक्चर निर्माण में भी बरती जा रही लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। प्रावधान होने के बावजूद नए स्ट्रक्चर नहीं बनाए जा रहे हैं। लापरवाही पर कई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है लेकिन वह भी अप्रभावी ही साबित हुई है। इससे 10 प्रतिशत ही वर्षा जल जमीन में जा पा रहा है।

(रा.प., 08.01.19)

धरती की कोख छीलने पर तुले अफसर

जल संसाधन और जलदाय विभाग के अफसर शहर के पेयजल संकट से निपटने को ब्राह्मणी नदी से पानी लाने के बजाय धरती की कोख छीलने पर उतर आए हैं। शहर में जलदाय विभाग की ओर से पहले ही 2064 नलकूपों से पानी खींचा जा रहा है, अब 453 नए नलकूप फिर खोदने की तैयारी है।

पांच माह पूर्व भी 552 नलकूपों की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में पांच माह में ही 1005 नलकूप लगाकर डार्कजोन में भूजल स्तर और गिराने की तैयारी है। शहर का भूजल स्तर पहले ही आधा मीटर गिर चुका है। सरकार और नौकरशाहों का ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध में पानी लाने के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर फोकस नहीं होने से ऐसे हालात पनप रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि जलदाय विभाग जिस गति से जमीन से पानी खेंच रहा है उससे साफ है कि 4-5 साल तक ही भूजल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इसके बाद बड़ी मुश्किल आने वाली है। *(रा.प., 07.01.19)*

मुफ्त में पी गए 106 करोड़ का पानी

कुछ उपभोक्ताओं के गैर जिम्मेदाराना रवैये का खामियाजा लाखों लोगों को उठाना पड़ता है। ऐसे ही हालात पेयजल उपभोग से जुड़े है। कुछ उपभोक्ताओं ने पानी का उपभोग तो कर लिया, पर शुल्क जमा कराने से बचते रहे हैं। इससे करीब 106 करोड़ रुपए बकाया हो गए।

जलदाय विभाग को आखिर ऐसे लोग अब जाकर याद आए हैं। ऐसे बकायादारों को तलाशने से लेकर उनसे राशि वसूलने के लिए संबंधित अभियंता-अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके अलावा शहर में 2.61 लाख उपभोक्ताओं के घर में लगे मीटर खराब हैं, जो कुल उपभोक्ताओं की करीब 61 प्रतिशत है। यह बड़ा आंकड़ा भी अफसरों को नींद से जगाने के लिए काफी है। इसके कारण से वास्तविक शुल्क की गणना नहीं की जा सकी है। *(रा.प., 12.02.19)*

जल संरक्षण में अव्वल रहा बारां

जल संरक्षण को लेकर देश के 101 इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पर रहे प्रदेश के बारां जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिले में पिछले तीन साल में जल संरक्षण को लेकर हुए कार्यों से भूमिगत जल स्तर में 5 फीट तक का इजाफा हुआ है।

दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी व केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बारां के पूर्व व सवाई माधोपुर कलेक्टर डॉ. एस.पी.सिंह व बारां कलेक्टर इंद्र सिंह राव को अवार्ड व प्रमाण-पत्र प्रदान किया।

गौरतलब है कि बारां में वर्ष 2015-16 से 30 जून 2018 तक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत 8101 कार्य हुए और इनसे औसत भूमिगत जल स्तर बढ़ा है, तब डॉ.एस.पी.सिंह बारां में कलेक्टर थे।

(दै.भा., 26.02.19)

समान रूप से होगी पेयजल सप्लाई

अब शहर के ज्यादातर पंप हाउस स्काडा सिस्टम से ऑटोमैटिक व ऑनलाइन कंट्रोल होंगे। इससे जलदाय विभाग के कर्मचारी किसी खास इलाके में कम या ज्यादा पेयजल सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब पाइपलाइन में सप्लाई होने वाले पानी का हिसाब भी रखा जाएगा, ताकि हर उपभोक्ता तक पानी पहुंचे।

पानी की छीजत की भी अब नए सिरे से गणना होगी। अमृत स्कीम में शहर के पंप हाउसों पर ऑटोमैटिक सिस्टम लगाए जा रहे हैं। बालावाला पंपिंग स्टेशन सहित अन्य पंप हाउसों पर कंट्रोल रूम होगा। स्काडा सिस्टम से हर क्षेत्र की पेयजल सप्लाई का समय तय किया जाएगा और पेयजल सप्लाई की सही तरीके से मॉनिटरिंग हो सकेगी। इस सिस्टम पर करीब पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे।

(दै.भा., 02.03.19)

अब लीकेज खोजने में जुटेगा विभाग

जलदाय विभाग के अनुसार जयपुर शहर में सप्लाई किए जा रहे पेयजल का 25 प्रतिशत हिस्सा छीजत (लीकेज व चोरी) में जा रहा है। पेयजल की किल्लत को देखते हुए विभाग अब लीकेज खोजने की मशक्कत करने जा रहा है। इसके लिए शहर के संबंधित सभी अधिशासी अभियंताओं के नेतृत्व में टीम गठित कर उन्हें उपकरण दिए गए हैं।

अधिक्षण अभियंता (उत्तर) को इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों का दावा है कि छीजत का पता लगने के बाद हर दिन लीकेज हो रहा करीब 12 से 15 करोड़ लीटर पेयजल बचाया जा सकेगा। पेयजल छीजत का पता लगाने के लिए सर्वे भी हो चुका है। सर्वे करने वाली एजेंसी के द्वारा 30 प्रतिशत तक छीजत होने का दावा किया गया है। *(रा.प., 15.02.19)*

महिला सशक्तिकरण पर फोकस

केंद्र सरकार के 2019-20 के अंतरिम बजट में महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। इस बार महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा के लिए कुल 1330 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। पिछले साल से 174 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किया जाएगा।

महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत दो करोड़ एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क बांटे जाएंगे। बताया गया है कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आठ करोड़ गैस कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य था जिसमें से छह करोड़ गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बाल विकास के लिए भी 4227 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान बजट में है।

प्रदेश में लेखानुदान के अनुसार सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर में अध्ययनरत छात्राओं को अब शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इनमें कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय शामिल हैं। नए सत्र से यह प्रभावी हो जाएगा।

पति से गिफ्ट मिली संपति स्टाम्प मुक्त

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला किया कि महिलाओं को उनके पति द्वारा उपहार में दी गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर अब स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। वर्तमान में पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन, पुत्रवधु, पति, पौत्र, पौत्री, नाती या नातिन को अचल संपत्ति गिफ्ट देने पर संपत्ति के बाजार मूल्य की ढाई प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है। पत्नी या बेटी के मामले में बाजार मूल्य की एक फीसदी या अधिकतम एक लाख तक स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान है। इनमें से जो भी कम हो, वह राशि देनी पड़ती है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अब पत्नी के मामले में स्टाम्प ड्यूटी पर पूरी छूट देने का निर्देश दिया है।

(दै.भा. एवं रा.प., 26.02.19)

महिलाओं को किया जाएगा जागरूक

प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं व बालिकाओं के लिए शुरू की गई माहवारी स्वच्छता प्रबंधन योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में इस योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने की कवायद की जा रही है।

योजना के तहत समुदाय में तथा स्कूलों में महिलाओं और किशोरियों को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर जागरूक किया जाएगा। पंचायत स्तर पर इससे जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा होगी। स्कूलों में तथा समुदाय में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं व किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे। इस काम में स्वयंसेवी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह, साथिन और चिकित्सा विभाग के कर्मचारी सहयोग करेंगे।

(दै.न., 10.01.19)

पंचायत मुख्यालय पर सीनियर स्कूल

सरकार ने प्रदेश के हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल खोलने की कवायद शुरू कर दी है। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को 12वीं तक की पढ़ाई के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।

पंचायत स्तर पर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल खुलने का सबसे ज्यादा फायदा बेटियों को मिलेगा। पिछली सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए थे, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में स्कूल क्रमोन्नत नहीं हो पाए। अब नई सरकार इस घोषणा को पूरा करने में लगी है।

(रा.प., 06.01.19)

बेटियों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सरकार बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना को अगले सत्र से लागू करेगी।

उन्होंने बताया कि सरकार प्रथम चरण में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव हैं। इसके बाद सब कुछ ठीक रहा तो सत्र 2020-21 से प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क मुहैया कराने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। *(दै.न., 05.01.19)*

राष्ट्रपति ने झुककर लिया आशीर्वाद

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब कर्नाटक की पर्यावरणविद् सालुमारदा थिमाक्का को पद्मश्री पुरस्कार दे रहे थे, तो बरबस ही सबकी आंखे उस पल पर जाकर टिक गई, जब 107 वर्षीय थिमाक्का दादी के हाथ राष्ट्रपति के सिर पर आशीर्वाद के लिए उठ गए। उन्होंने समारोह में राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया।

पेड़ों की मां के नाम से चर्चित थिमाक्का ने अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों को पालने-पोसने में ही खपा दी। उनके बच्चे नहीं हुए तो वह पेड़ों को बेटा मानने लगी। उन्होंने करीब 8000 पेड़ लगाए और उन्हें बच्चों की तरह पाल-पोषकर बड़ा भी किया। उनका सबसे उल्लेखनीय काम करीब 400 बरगद के पेड़ लगाना रहा। ये पेड़ हुल्लूर और कुदूर के बीच हाइवे पर करीब चार किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। धरती की हरियाली बढ़ाने वाली इस दादी का हर शख्स शुक्रगुजार है।

(रा.प., 17.03.19)

देश की आधी महिलाएं खून की कमी की शिकार

भारत में महिलाओं की आधी से ज्यादा आबादी आज भी खून की कमी (एनिमिया) से जूझ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के शोध के अनुसार सही पोषण और स्वास्थ्य उपायों के अलावा महिलाओं में शिक्षा की कमी इसकी मुख्य वजह है। शोधकर्ता भारत आधारित नेशनल फैमेली हेल्थ सर्वे 2005-06 और 2015-16 के आंकड़ों का अध्ययन कर इस नतीजे पर पहुंचे हैं।

सर्वे के अनुसार भारत में मां बनने योग्य आयु वर्ग की 53 फीसदी महिलाएं खून की कमी यानी एनिमिया की शिकार हैं। शरीर में आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है, जिससे खून में इसकी कमी हो जाती है। इससे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती। *(रा.प., 20.02.19)*

सड़क सुरक्षा

हर साल 90 करोड़ खर्च, मात्र एक फीसदी घटी मौतें

परिवहन-पुलिस सहित कई विभागों के साझा प्रयासों के बाद भी प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में मौतों में महज एक फीसदी और घायलों में दो फीसदी की ही कमी आई है। यह हालात तब हैं, जब परिवहन विभाग को सड़क दुर्घटना रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नोडल विभाग बनाया गया है।

साथ ही तीन साल पहले परिवहन मुख्यालय में इस संबंध में 10 अधिकारी व कर्मचारियों को शामिल कर अलग रोड सेफ्टी विंग भी बनाई गई। लेकिन 90 करोड़ रुपए का सालाना बजट पाने वाली रोड सेफ्टी विंग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश में मौतों के आंकड़ों पर गौर करें तो 13 जिलों में महज 10 प्रतिशत की ही कमी आई है। वहीं 16 ऐसे जिले हैं, जहां पिछले साल के मुकाबले मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। विभागों में सामंजस्य नहीं होने से यह नतीजे सामने आ रहे हैं। यह स्थिति राज्य में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के प्रयासों पर सवाल खड़े करती है। *(रा.प., 21.01.19)*

जन स्वास्थ्य

सेहत का ख्याल, नब्ज पर रखा हाथ

केंद्र के बजट में लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए पिछले तीन सालों की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल जहां 54302.50 करोड़ रुपए का चिकित्सा क्षेत्र के लिए प्रावधान था वह 2019-20 के अंतरिम बजट में 61398.12 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अर्थात 7096 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। प्रभारी वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने आयुष्मान योजना का बखान करते हुए बताया कि इससे 10 लाख करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है तथा वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा।

इधर, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, हृदय, गुर्दा रोग व सांस की बीमारियों की सभी दवाओं को शामिल करते हुए कहा है कि इससे बड़ी बीमारियों के इलाज में आमजन को बड़ी राहत मिल सकेगी। निःशुल्क दवा योजना के तहत 600 नए दवा वितरण केंद्र खोलने और प्रदेश में बड़ी संख्या में नई जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा करते हुए कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाया जाएगा। जोधपुर कॉलेज के संक्रामक रोग अस्पताल को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

सरकारी अस्पताल में गारंटेड इलाज

प्रदेश में सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में किए वादे 'स्वास्थ्य का अधिकार' पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार मिले। इसका मसौदा 22 राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पार्टनर मिलकर तैयार करेंगे। इसे 'एश्योर डिलीवरी ऑफ क्वालिटी सर्विसेज' का नाम दिया गया है।

मसौदे का सबसे बड़ा बिन्दु गारंटेड गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराना होगा। संभवतया सरकार यह गारंटी भी देगी कि हर ग्राम पंचायत पर एक सब-सेंटर होगा। तय आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल होगा। इसके लिए पैरामीटर तय होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। *(रा.प., 05.01.19)*

पर्यावरण

बढ़ता जा रहा है जलवायु परिवर्तन का खौफ

गत 50 साल में जलवायु में हुए बदलाव का खौफ विश्व के कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। वर्तमान में विश्व की 7.7 अरब जनसंख्या में से 2 अरब जनसंख्या कुपोषण की शिकार है, जबकि 80 करोड़ जनसंख्या भुखमरी से जकड़ी हुई है। वर्ष 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर 10 अरब को पार कर जाएगा।

शुष्क भूमि विकास के लिए जोधपुर में हुए विश्व के 13वें चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 35 देशों के 450 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों और स्कॉलर्स ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया।

सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे पर्यावरण बदलाव से कृषि में उत्पादन एक चौथाई तक कम होने की आशंका कृषि विशेषज्ञों के लिए खास चिंता का विषय रहा। ग्लोबल वार्मिंग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1990 से 2017 के दौरान पूरा विश्व हजारों करोड़ रुपए जलवायु परिवर्तन से जूझने में खर्च कर चुका है।

सम्मेलन में वैज्ञानिकों और स्कॉलर्स के सामने विश्वभर में फैली 41 प्रतिशत शुष्क भूमि को हरी-भरी करने की चुनौती साफ नजर आई। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटलीजेंस, कम्प्यूटर सिमयूलेशन, ई-कृषि, बिग डाटा एनालिसिस व रिमोट सेंसिंग की मदद से समस्या को हल कर अनाज का उत्पादन बढ़ाने की सलाह दी है। *(रा.प., 12.02.19)*

वित्तीय सेवाएं

अपने फंसे कर्ज को बेचेंगे बैंक!

सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक अपने फंसे कर्ज को बेचने की योजना बना रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट (एनसीएलटी) में चल रहे मामले भी शामिल हैं। बैंकों के इस कदम का मकसद वित्त वर्ष 2019-20 में अपने खाते में दबाव वाली संपत्तियों का बोझ कम करना है। दिवालिया प्रक्रिया की सुनवाई धीमी गति से चल रही है और कई मामले कानूनी दाव-पेच की वजह से निर्धारित 270 दिन की समयसीमा से पार पहुंच गए हैं।

मुकदमों की वजह से एनसीएलटी में मामलों के लंबे समय से अटकने की वजह से बैंक अब अपने खाते को दुरुस्त करने के लिए उपाय तलाश रहे हैं। कई बैंक अभी इंतजार कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि एनसीएलटी में समाधान किस तरह से होता है। बैंकों के अधिकारियों का कहना है कि इस समय फंसे कर्ज को बेचने का निर्णय सही है। *(रा.प., 25.01.19)*

उपभोक्ता फैसले

दोषयुक्त जेसीबी मशीन बेची, देना होगा सवा लाख रुपए हर्जाना

जयपुर स्थित जमवा रामगढ़ के नेवर गांव निवासी रमेश चन्द मीणा ने राज्य उपभोक्ता आयोग में नेशनल मोटर्स, झोटवाड़ा तथा महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कन्स्ट्रक्शन इक्यूपमेंट, मुम्बई के खिलाफ अपने वकील के जरिए 21 अप्रेल 2016 को परिवाद दर्ज कराया। उनके वकील ने आयोग को जानकारी दी कि निजी व घरेलू जीविकोपार्जन के लिए रमेश चन्द ने महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा द्वारा निर्मित जेसीबी अर्थमास्टर 30 नवम्बर 2013 को 22 लाख 90 हजार रुपए में झोटवाड़ा स्थित नेशनल मोटर्स से खरीदी थी। कुछ समय तक मशीन मिट्टी खुदाई में तो ठीक-ठाक चली, लेकिन कठोर भूमि पर चलाते ही खराब हो गई। उनसे मशीन ठीक करने व नए पार्टस के नाम पर हजारों रुपए वसूले गए, लेकिन बार-बार सही कराने पर भी मशीन ने कार्य क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं किया। इससे परिवादी को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।

मामले की सुनवाई पर विपक्षी की ओर से कहा गया कि खुदाई के लिए लिया गया पंजा केवल मिट्टी खोदने का था, कठोर व पथरीली जगह के लिए अलग पंजा काम में लेना चाहिए था। आयोग ने अत्यधिक गुणवत्ता वाली मशीन के गारंटी-वारंटी अवधि में ही बार-बार खराब होने को सेवा दोष माना। आयोग ने नेशनल मोटर्स तथा महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कन्स्ट्रक्शन इक्यूपमेंट को आदेश दिया कि वह रमेश चन्द मीणा को सवा लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करें। साथ ही 15 दिन में मशीन की खराबी की विशेषज्ञ से जांच करवाए और निःशुल्क ठीक कराकर सुपुर्द करें। *(स.ज., 07.02.19)*

पेट में छोड़ दी थी कैंची, अब देना होगा छह लाख रुपए का हर्जाना

बीकानेर निवासी पूनम ने जिला उपभोक्ता मंच में डॉ. इति माथुर, टी. फिलिक एवं माथुर हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर, रानी बाजार के खिलाफ परिवाद दायर किया। परिवाद में कहा गया कि वह गर्भवती थी। उसने 25 फरवरी, 2013 को रानी बाजार निवासी डॉ. इति माथुर से जांच कराई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और डॉ. इति माथुर ने ऑपरेशन किया। उसने बच्ची को जन्म दिया। घर आने के बाद पूनम के पेट में दर्द रहने लगा। डॉ. इति माथुर को दिखाया तो उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं हैं। लेकिन दवाइयां लेने के बावजूद दर्द कम नहीं हुआ तो पीबीएम अस्पताल में अन्य चिकित्सक को दिखाया। तब पता चला कि उनके पेट में कैंची छोड़ दी गई थी। पीएनबी अस्पताल में 16 मार्च, 2013 को ऑपरेशन कर उसके पेट से कैंची निकाली गई।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने इसे लापरवाही से भरा व महिला का जीवन खतरे में डालने वाला गंभीर सेवा दोष माना। मंच ने महिला चिकित्सक इति माथुर को आदेश दिया है कि वह पूनम को छह लाख रुपए बतौर हर्जाना दें। साथ ही परिवाद व्यय के रूप में दस हजार रुपए अलग से दिए जाएं। राशि का भुगतान एक महीने में करना होगा।

(रा.प., 27.02.19)

खास समाचार

सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत 'कट्स' एवं इटर्नल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में यातायात पुलिस के सहयोग से गुड सेमेरिटन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन पर इटर्नल हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में सेमिनार आयोजित की गई। कार्यक्रम में यातायात डीसीपी पूजा अवाना ने लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट और गुड सेमेरिटन (अच्छा मददगार) की उपयोगिता पर जोर दिया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा से संबंधित पोस्टर का विमोचन भी किया गया।

इटर्नल हॉस्पिटल की को-चेयरपर्सन एमडी मंजू शर्मा ने कार्यशालाओं व नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने तथा बच्चों को यातायात नियमों का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। सेमिनार में डॉ. सुशील तापड़िया, पीपुल्स ट्रस्ट की प्रेरणा अरोड़ा, 'कट्स' के डिप्टी डायरेक्टर दीपक सक्सेना व मधुसूदन शर्मा ने भी अपने विचार रखे। इसी क्रम में अजमेरी गेट स्थित यादगार से जागरूकता रैली भी निकाली गई जिसमें यातायात पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक वार्डन आदि सम्मिलित हुए। उन्होंने चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बैल्ट लगाने को जागरूक किया। साथ ही अलबर्ट हॉल पर सड़क सुरक्षा से संबंधित नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259
फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org